



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार ११ फरवरी, १९९७/२२ मार्च, १९१८

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-२, २९ जनवरी, १९९७

संख्या जी०ए०डी०(पी०ए०)(४ डी)१०/८८—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा अनुपूरक उपबन्ध अधिनियम, १९८१ की धारा ३ के अधीन "हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के (मोटर कार अधिनियम) नियम,

1971" का प्राधिकृत राजभाषा हिन्दी पाठ राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के सहर्ष आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा,
एस0 एस0 नेगी,
प्रायुक्त एवं सचिव।

हिमाचल प्रदेश मन्त्री (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मन्त्री (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971 है।

(2) ये नियम 25 जनवरी, 1971 से प्रवृत्त रामझे जाएंगे।

2. परिभाषा.—इन नियमों में जब तक कि विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो :—

(i) "अधिनियम" से (हिमाचल प्रदेश) मन्त्री के वेतन और भत्ता अधिनियम, 1971 अभिप्रेत है ;

(ii) "मन्त्री" से किसी भी नाम से ज्ञातव्य मन्त्री-परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है ;

(iii) "मंजूरी प्राधिकारी" से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(iv) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. अनुज्ञेय अग्रिम.—मन्त्री को मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम दिया जा सकेगा ताकि वह अपने कार्यालय के कर्तव्यों को, इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, सुविधा पूर्वक तथा दक्षता पूर्वक निर्वहन कर सकें।

4. अधिकतम अग्रिम राशि.—मोटर कार के क्रय हेतु मन्त्री को अधिकतम राशि छः लाख रुपये या खरीदी जाने वाली मोटर कार की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश मन्त्री (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1981 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम 1981 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1979 के नियम 4 के अधीन भवन निर्माण अग्रिम लिया हो तो मोटर कार अग्रिम की कुल राशि की परिसीमा मन्त्री द्वारा पहले से ही लिए गए भवन निर्माण अग्रिम सहित छः लाख रुपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि जहाँ मन्त्री ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उपमन्त्री या विधान सभा सदस्य, यथास्थिति, की हैसियत में मोटर कार अग्रिम ले रखा हो तो मोटर कार की कुल राशि की परिसीमा उसे पहले दिए गए मोटर कार अग्रिम सहित छः लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

5. अग्रिम की वसूली.—(1) नियम 4 के अधीन मंजूर अग्रिम की वसूली उस पर ब्याज सहित 120 समान मासिक किस्तों में दी जाएगी सरकार शेष पदावधि को ध्यान में रखते हुए या यदि मन्त्री स्वयं ऐसा चाहे तो कम संख्या की किस्तों में वसूली के आदेश कर सकती। कटौती, अग्रिम लेने के पश्चात् पहले जारी वेतन से प्रारम्भ की जाएगी।

(2) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली उसी प्रकार की अग्रिम राशि पर समय-समय पर नियत किये जाने वाला साधारण ब्याज बसूल किया जाएगा, परन्तु अग्रिम राशि लेने के समय नियत की गई ब्याज दर अग्रिम के पूरे समय तक वही लागू रहेगी।

(3) यदि कोई मन्त्री अग्रिम धनराशि पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व ही किसी कारणवश मन्त्री पद पर नहीं बना रहता परन्तु विधान सभा का सदस्य बना रहता है तो मासिक किस्तें उसे विधान सभा सदस्य के रूप में अनुज्ञेय विभिन्न भत्तों में से विधान सभा सचिवालय द्वारा बसूल की जाएगी।

(4) यदि कोई मन्त्री अग्रिम धनराशि के पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व विधान सभा सदस्य के पद पर नहीं बना रहता परन्तु पेंशन का हकदार होता है तो उसे भिजने वाली पेंशन में से विधान सभा सचिवालय द्वारा बसूली की जाएगी तथा मासिक किस्तों की बकाया राशि उसके द्वारा नियमित रूप से सरकारी कोष में जमा की जाएगी और इस भुगतान के प्रमाण के रूप में वह चाहे तो एक प्रति सरकार को नियमित रूप से प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि वह विधान सभा सदस्य के पद पर नहीं रहता तथा पेंशन का हकदार भी नहीं बनता तो उसके द्वारा मासिक किस्तें उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित नियमित रूप से प्रति मास सरकारी कोष में जमा की जाएगी तथा इसके प्रमाण में कोष के चालान की प्रति सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(6) अग्रिम धनराशि तथा उस पर प्रोदभूत ब्याज की बसूली से पूर्व ही मृत्यु होने की दशा में मन्त्री या विधान सभा सदस्य का विधिक उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी द्वारा अग्रिम पर प्रोदभूत ब्याज सहित अग्रिम की शेष राशि एक मुश्त सरकारी कोष में जमा करेगा, और वह/वे समस्त राशि के जमा किए जाने के प्रमाण में चालान की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत करेगा/करेंगे।

(7) यदि मन्त्री या उसका विधिक प्रतिनिधि, यथास्थिति, अग्रिम के मूलधन उस पर ब्याज की मासिक किस्तों की नियमित अदायगी नहीं करता या यदि वह/वे दिवालिया हो जाता है/जाते हैं या ऋण की अदायगी के नियमों तथा शर्तों के अनुपालन या पालन करने में विफल होता है/होते हैं तो इस दशा में ऋण की सम्पूर्ण मूल राशि या उसमें से इतना जितना कि उस समय देय तथा असंदत रहा हो सरकार को उस पर निहित दर से ब्याज सहित एक मुश्त में तत्काल देय होगा। सरकार को उपरोक्त बकाया राशि को "भू-राजस्व के बकाया" के रूप में बसूल करने की स्वतन्त्रता होगी। विधान सभा सचिवालय द्वारा इस प्रभाव में की गई बसूली उपरोक्त शर्तों पर विचार करते हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (मोटर कार के क्रय के लिए ऋण अग्रिम) नियम, 1979 जैसा समय-समय पर प्रवृत्त हो के अधीन विनियमित की जाएगी।

स्पष्टीकरण.—मासिक रूप में बसूल की जाने वाली अग्रिम धनराशि की अन्तिम किस्त, जिसमें शेष राशि रुपये के किसी अंश सहित बसूल की जानी है, को छोड़कर, पूरे रुपये में नियत की जाएगी।

6. मोटर कार का विक्रय.—(1) मन्त्री के पद त्याग देने के सिवाय अग्रिम की सहायता से खरीदी गई मोटर कार को बेचने के लिए मन्त्री द्वारा सरकार की पूर्व मंजूरी ली जाएगी, यदि ऐसा अग्रिम उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित पूर्णतः प्रति संदाय नहीं किया गया हो। यदि मन्त्री मोटर कार और उसके दायित्व को किसी अन्य मन्त्री को अन्तरित करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की सरकार के आदेशों से अनुमति दी जा सकेगी परन्तु यह और कि खरीदने वाला मन्त्री एक घोषणा अभिलिखित करेगा कि उसे जानकारी है कि उसे अन्तरित की गई मोटर कार सरकार के पास बंधक के अहमधीन रहेगी और यह कि कार को अन्तरित करने वाले मन्त्री द्वारा निष्पादित बंधक-पत्र के निबन्धनों और उपायों नियम-8 के अधीन आवद्ध कर होगा।

(2) सभी मामलों में जब मोटर कार अग्रिम को उस पर ब्याज सहित पूर्णतः प्रतिसंदाय से पहले ही बेच दी जाती है तो ऐसे बकाया अतिशेष के प्रतिसंदाय हेतु जहां तक आवश्यक हो विक्रय आगम उपयोजित होगा:

परन्तु जब मोटर कार इसलिए बेची गई हो कि अन्य दूसरी मोटर कार खरीदी जा सकेगी सरकार मन्त्री को निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसी खरीद हेतु विक्रय अग्रिम को प्रयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी अर्थातः—

(क) परादेय राशि को नई कार की लागत से अधिक होने की अनुज्ञा नहीं होगी ;

(ख) परादेय राशि को प्रतिसंदाय पूर्व नियत दर से जारी रहेगा; और

(ग) नई कार सरकार के पास बन्धक और बीमाकृत भी होगी ।

7. अवधि जिसके भीतर कार खरीदने के लिए वार्ता पूर्ण की जा सकेगी.—मन्त्री जो मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम लेता है खरीदने के लिए वार्ता पूर्ण करेगा और अग्रिम लेने की तारीख के एक महीने के भीतर मोटर कार के लिए पूर्ण अदायगी करेगा । ऐसी सम्पूर्ति और अदायगी के न होने पर अग्रिम की सम्पूर्ण राशि उस पर एक महीने के ब्याज सहित सरकार को वापिस की जाएगी । व्यक्तिगत की दशा में सरकार द्वारा व्यवहार की सम्पूर्ति के लिए फिर भी एक महीने की अवधि में छूट दी जा सकेगी । जब मोटर कार पहले ही खरीदी गई हो और पूरा संदाय कर लिया हो अग्रिम अनुज्ञेय नहीं होगा । उस दशा में जिसमें अदायगी भागतः की हो तो अग्रिम की राशि असंदत बकाया तक ही सीमित होगी जैसा मन्त्री द्वारा प्रमाणित किया गया हो ।

8. करार का निष्पादन.—अग्रिम लेते समय मन्त्री प्रारूप I में करार निष्पादित करेगा और खरीद पूर्ण होने पर जिसमें वह अग्रिम के लिए सरकार को प्रतिभूति के रूप में मोटर कार को आडमान करते हुए प्ररूप II में बन्धक-पत्र निष्पादित भी करेगा । मोटर कार की लागत कीमत बन्धक-पत्र के साथ संलग्न अनुसूची के विनिर्देशों में दर्ज की जाएगी ।

टिप्पणः—करार प्रारूप सादे आगज पर निष्पादित किए जाएंगे और लिखत पर स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रीकरण प्रभार यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे ।

9. संपरीक्षा अधिकारी को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना.—जब अग्रिम लिया जाता है, मंजूरी प्राधिकारी, संपरीक्षा अधिकारी को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि अग्रिम लेने वाले मन्त्री ने प्ररूप II में करार को हस्ताक्षरित कर लिया है और यह नियमानुसार है । मंजूरी प्राधिकारी देखेगा कि मोटर कार अग्रिम लेने की तारीख से एक महीने के भीतर या ऐसी अवधि में जैसे नियम 7 के अधीन कारंवाई सम्पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा वैयक्तिक मामलों में विनिर्दिष्टतया अनुज्ञात की जा सकेगी खरीद ली गई है और प्रत्येक बन्धक-पत्र को तत्परता से संपरीक्षा अधिकारी को अन्तिम अभिलेख से पूर्व परीक्षण के लिए रखेगा ।

10. सुरक्षित अभिरक्षा और बन्धक-पत्र का रद्द किया जाना.—बन्धक-पत्र मंजूरी प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा । जब अग्रिम का उस पर ब्याज सहित पूर्ण रूप में प्रतिसंदाय कर लिया जाता है तो बन्ध-पत्र संपरीक्षा अधिकारी से अग्रिम और ब्याज के सम्पूर्ण प्रतिसंदाय का प्रमाण पत्र प्राप्त करके सम्यक् रूप से रद्द करके सम्बद्ध मन्त्री को वापिस किया जाएगा ।

11. अग्रिम से खरीदी गई मोटर कार का अग्नि, चोरी या दुर्घटना द्वारा पूर्ण हानि के विरुद्ध किसी साधारण बीमा कारबार करने वाली कम्पनी/बीमा निगम के साथ बीमा किया जाएगा । बीमा पालिसी में प्रारूप III के अनुसार खण्ड होगा जिसमें निगम स्वामी की अनेका सरकार को मोटर कार को हुई हानि या क्षति, जिसकी प्रतिपूर्ति, मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है देने का करार करती है । ऐसा बीमा क्रय की तारीख के एक महीने के भीतर प्रभावी होगा ।

12. हिमाचल प्रदेश मन्त्री (ऋण और ग्रग्रिम) नियम, 1967 के अनुसार मोटर कार की खरीद के लिए ग्रग्रिम के रूप में किए गए सभी भुगतान और की गई कोई बात या कार्रवाई विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

प्ररूप—I

मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम लेते समय निष्पादित किए जाने वाले करार का प्ररूप—I

(नियम 8 देखें)

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री.....मन्त्री हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें आगे उधार लेने वाला कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "सरकार हिमाचल प्रदेश" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पदांतरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख.....को किया गया है ।

उधार लेने वाले ने हिमाचल प्रदेश मन्त्री (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971 के अधीन मोटर कार खरीदने के लिए सरकार कोरु0 (.....रुपये) के ऋण के लिए आवेदन किया है और सरकार इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट निबन्धनों और शर्तों पर उधार लेने वाले को उधार देने के लिए सहमत हो गई है ।

(2) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उधार लेने वाले को.....रु0 (.....रुपये) की संदत्त राशि के प्रतिफल में पक्षकारों के बीच करार किया जाता है (उधार लेने वाला जिसकी पावनी की अभिस्वीकृति करता है) उधार लेने वाला सरकार के साथ करार करता है कि—

- (i) जैसा उक्त नियम द्वारा उपबन्धित है उसे विधान सभा सदस्य के रूप में संदेय वेतन या भत्ते, पेंशन से.....मासिक कटौतियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार संगणित ब्याज सहित कथित राशि को सरकार को संदत्त करेगा (जितनी अधिक बसूल की जा सके और शेष उसके द्वारा सरकारी कोष में जमा की जाएगी और सरकार को ऐसी कटौतियां करने को प्राधिकृत करता है यदि उधार लेने वाला पेंशन लेने का हकदार न हो तो प्रोदभूत ब्याज सहित मासिक किस्त उसके द्वारा नियमित रूप से सरकारी कोष में जमा की जाएगी तथा वह सरकार को उक्त नियमों में यथा उपबन्धित जमा की गई राशि के साक्ष्य स्वरूप चानान की प्रति प्रस्तुत करेगा),
- (ii) मोटर कार की खरीद में उक्त ऋण की पूर्ण राशि को व्यय करने या यदि संदत्त वास्तविक कीमन ऋण से कम हो तो उनके अन्तर का प्रतिसंदाय सरकार को इन विलेखों की तारीख से एक मास के भीतर तत्काल करेगा, और
- (iii) उधार लेने वाले को यथा पूर्वोक्त उधार दी गई राशि के लिए सरकार के पास प्रतिपूर्ति के रूप में उक्त मोटर कार के आड़मान करने वाले दस्तावेजों और उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित प्ररूप में ब्याज का निष्पादन करेगा ।

इसके द्वारा अन्त में यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि इन विलेखों की तारीख से एक महीने के भीतर पूर्वोक्त रूप में मोटर कार का आड़मान नहीं की जाती या उधार लेने वाला उस अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या पद त्याग देता है अथवा मन्त्री नहीं रहता या उसकी मृत्यु हो जाती

है ऋण की पूरी राशि उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित तुरन्त शोध और संदेय हो जाएगी। सरकार उक्त परादेय की राशि को "भू-राजस्व की बकाया" के रूप में बसूल करने के लिए स्वतन्त्र होगी।

इसके साक्ष्य स्वरूप उधार लेने वाले ने पहले लिखे दिन और तारीख को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त श्रीने

.....
.....

हस्ताक्षर (नाम और पद)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

.....
(अधिकारी के हस्ताक्षर और पद नाम)

1.....

2.....

साक्षी के हस्ताक्षर

उधार लेने वाले का नाम और पदनाम—

.....की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

प्ररूप—II

मोटर यान अग्रिम के लिए बन्धक-पत्र का प्ररूप

(नियम 8 देखें)

यह कशर एक पक्षकार के रूप में श्री.....जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, समनुदेशिनी और विधिक प्रतिनिधि भी है और दूसरे पक्षकार के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "हिमाचल प्रदेश सरकार" जिसके अन्तर्गत उसके पदोत्तरधर्ती और समनुदेशिनी भी हैं) के बीच आज तारीख.....को किया गया है।

उधार लेने वाले ने.....रु० (केवल.....रुपये) के लिए आवेदन किया है और (हिमाचल प्रदेश) मन्त्री वेतन और भत्ते अधिनियम, 1971 के अधीन बनाए गए हिमाचल प्रदेश मन्त्री (मोटर कार अग्रिम)नियम, 1971 (जिन्हें इसमें इसके आगे "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 और 4 के अनुसार मोटर कार खरीदने के लिए.....रुपये का अग्रिम प्रदान किया गया है और एक शर्त जिस पर उधार लेने वाले को उक्त अग्रिम प्रदान किया गया है/था ये है/थी कि उधार लेने वाला उक्त मोटर कार को हिमाचल प्रदेश सरकार के पास उधार लेने वाले को दो गई राशि के लिए प्रतिभूति के रूप में आड़मान करेगा और उधार लेने वाले ने यथा पूर्वोक्त ऐसी अग्रिम राशि के पूर्ण या अंशतः भाग से मोटर कार खरीद ली है जिसका विवरण निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट है।

यह करार इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए उधार लेने वाला हिमाचल प्रदेश सरकार को.....रुपये (.....रुपये) की पूर्वोक्त राशि या उसके बचे हुए असंदत अवशेष को इस विलेख की तारीख तक.....रुपये (.....रुपये) की राशि के समान संदाय द्वारा प्रत्येक माम के प्रथम दिन को देगा और तत्समय देय शेष राशि पर व्याज संदत्त करेगा और बकाया संगणना उक्त नियम के अनुसार करेगा और उधार लेने वाला यह करार करता है कि ऐसा संदाय.... द्वारा उसके वेतन से उक्त नियमों में उपबधित रीति में विधान सभा सदस्य के रूप में संदेय वेतन या भत्तों या पेंशन से या अन्यथा मासिक कटौतियों द्वारा वसूल किया जा सकेगा, और उक्त करार के अनुसरण में उधार लेने वाला आगे हिमाचल प्रदेश सरकार को उक्त अग्रिम और उक्त नियमों द्वारा उस पर अपेक्षित व्याज सहित प्रतिभू के रूप में मोटर को समनुदेशित और अन्तर्गुह्य करता है जिसका विवरण नीचे लिखी अनुसूची में दिया गया है, इसमें उधार लेने वाला यह करार करता है और घोषणा करता है कि उसमें उक्त मोटर कार की पूर्ण क्रय कीमत संदत्त कर दी है और वह अब उसकी आत्यंतिक सम्पत्ति है और उसने उसे गिरवी नहीं रखा है और उक्त अग्रिम के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार को देय धन का बकाया जितने समय तक रहता है वह उस समय तक उक्त मोटर कार को न तो बेचेगा, न गिरवी रखेगा या न उस सम्पत्ति में या कब्जे को बिलग करेगा, सर्वथा यह करार और घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन या व्याज की कोई उक्त किस्तें उसके देय होने से दस दिन के भीतर उक्त रीति में संदत्त या वसूल नहीं की जाएगी या उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या मोटर कार को विक्रय करता है या गिरवी रखता है या उसे कब्जे से अलग करता है या दिवालिया हो जाता है या उसके किसी ऋणी से समझौता या अन्य व्यवस्था करता है या उधार लेने वाले के विरुद्ध किसी डिक्री या निश्चय के निष्पादन में कार्यवाही करता है, तब उक्त रूप में संगणित व्याज सहित समस्त उक्त मूलधन देय और असंदत्त हो, तुरन्त संदेय होगी।

यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इसमें पूर्व वर्णित किसी घटना के घटित होने पर उक्त मोटर कार का अभिग्रहण कर सकेगी और उसे हिलाए या बिना हिलाए अपने कब्जे में रख सकेगी या उक्त मोटर कार को लोक निलामी द्वारा या निजि विनिदा द्वारा विक्रय कर सकेगी और विक्रय राशि में से असंदत्त और यथा पूर्वोक्त संगणित देय व्याज सहित शेष अग्रिम और उचित रूप में उपगत सभी लागतों, प्रभारी व्ययों और इसके अधीन उनके अधिकार को बनाए रखने, अभिरक्षा करने और उगाहने के लिए किए गए या उपयुक्त रूप में उपगत संदाय रखेगी और अतिशेष यदि कोई हो उधार लेने वाले उसके निष्पादक, प्रशासक या वैयक्तिक प्रतिनिधि को संदत्त करेगी।

परन्तु यह और कि पूर्वोक्त कब्जा लेने वाली या उक्त मोटर कार को विक्रय करने की शक्ति, उधार लेने वाले या उसके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध उक्त उपशेष बकाया का देय और व्याज या मोटर कार को बेचे जाने की दशा में राशि जिसके द्वारा शुद्ध विक्रय आगम देय राशि से कम पड़ते हों, के बारे में मुकद्दमा चलाने के हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

उधार लेने वाला आगे यह करार करता है कि जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई धन शोष्य और बकाया रहता है उधार लेने वाला उक्त मोटर कार को अग्नि, चोरी, दुर्घटना द्वारा हानि के विरुद्ध किसी सामान्य बीमा कारबार करने वाली किसी बीमा कम्पनी/निगम के साथ बीमा करेगा और संपरीक्षा अधिकारी के समाधान के लिए यह साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि सामान्य बीमा कारबार करने वाली बीमा कम्पनी/निगम में जिसके साथ उक्त मोटर कार बीमाकृत है ने सूचना प्राप्त कर ली है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पालिसी में हितवद्ध है।

उधार लेने वाला और यह करार भी करता है कि उक्त मोटर कार को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं होने देगा या उस मात्रा से अधिक क्षय नहीं होने देगा जो उसके युक्तियुक्त टूट-फूट से होती हो और आगे यह कि उक्त मोटर कार को किसी हानि या दुर्घटना घटने की दशा में उधार लेने वाला तुरन्त उसकी मरम्मत करेगा और नुकसान को पूरा करेगा।

अनुसूची

मोटर कार का वर्णन
 बनाने वाले का नाम
 वर्णन
 सिलेण्डरों की संख्या
 ईंजन संख्या
 चैसिस संख्या
 लागत कीमत

इसके साक्ष्य स्वरूप उक्त..... (उधार लेने वाले का नाम) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से उक्त श्री..... ने उपरलिखित दिन और वर्ष को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

उक्त उधार लेने वाले..... ने

- 1..... (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
2. (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से श्री..... ने

1. (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
2. (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

(अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम)

प्रारूप-III

बीमा पालिसी में जोड़े जाने वाले खण्ड के प्रारूप

(नियम II देखें)

यह घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि श्री..... ने जो मोटर कार का स्वामी है जिसे इसमें आगे इस पालिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) के पास मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में ग्राहमान कर दिया है और यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि उक्त सरकार ऐसे धन में भी हितबद्ध है जो यदि यह पृष्ठांकन न होता तो उक्त श्री.....

(इस पालिसी के अधीन बीमाकृत को उक्त मोटर कार की हानियां उसका हुए नुकसान की बात जिस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति मुरम्मत, या पूर्वकरण या प्रति स्थापना द्वारा नहीं की गई) को संदेय होगा और ऐसा धन सरकार को उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वह मोटर कार की बन्धकदार है और उनकी रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी हानि या नुकसान की बाबत निगम ने पूरा और अन्तिम भुगतान कर दिया है ।

2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो करार किया गया है उसके सिवाय इसकी किसी भी बात से बीमाकृत के या कम्पनी के, इस पालिसी के अधीन या सम्बन्ध में अधिकार या दायित्व का अथवा इस पालिसी के किसी निबन्धन, उपबन्ध या शर्त का न तो उपान्तरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा ।

शिमला-171002, 29 जनवरी, 1997

संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी)/21/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा अनुपूरक उपबन्ध अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन "हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता नियम, 1971" का प्राधिकृत राजभाषा हिन्दी पाठ राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के सहर्ष आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा,

एस० एस० नेगी,
आयुक्त एवं मंचिव।

हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता नियम, 1971

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता नियम, 1971 है।
2. यह 25 जनवरी, 1971 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
3. सरकारी कार्य से मंत्री जब रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करें तो:—

- (क) प्रथम श्रेणी कूपा या यदि यह उपलब्ध न हो तो तब चार वर्ष वाला कम्पार्टमेंट या वाना-नुकूल डिब्बे में एक कूपा या शिमला और कालका के बीच रेलकार में एक सॉट;
- (ख) आनुषंगिक व्यय के लिए प्रति दस किलोमीटर या उसका भाग यदि वह पांच किलोमीटर से अधिक है, के लिए 35 पैसे की दर से भत्ता ;
- (ग) छः से अनाधिक व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम श्रेणी दरों पर वास्तुतः संदत्त किया गया रेलगाड़ी का किराया, चाहे वह उसके साथ यात्रा करें या पहले जाय या बाद में जाएं ;
- (घ) उपभोग के लिए ले जाए जाने वाला भण्डार सहित सभी वैयक्तिक चीज वस्तुओं का प्रवहन चाहे वह रेलगाड़ी सामान वैन में या अन्य रेलगाड़ी या सड़क द्वारा ले जाने;
- (ङ) मोटर कार का प्रवहन जब वह लोक हित में की गई यात्रा में नियोजित रही हो, का पूर्व व्यय और जहां सराहनीय तक व्यक्तिगत सुविधा सेवा की हो तब वहन का चार-पांच भाग व्यय ;
- (च) सरकारी कारणों से यात्रा के रद्द हो जाने पर टिकट रद्दकरण के कारण किराया प्रति-दाय करते समय रेलगाड़ी द्वारा की गई कटौती ;
- (छ) वर्णित रियायतों के अतिरिक्त मंत्री, रेल द्वारा यात्रा के लिए, मुख्यालय से प्रस्थान के दिन और पहुंचन के दिन के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा।

टिप्पण (1).—यदि किसी एक दिन पर दो विभिन्न यात्राएँ की गई हैं एक मुख्यालय पर समाप्त होने वाली और अन्य प्रारम्भ होने वाली तब दोनों यात्राओं के लिए केवल एक दैनिक भत्ता ही अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण (2).—इन नियमों में जहां प्रथम श्रेणी वास-सुविधा निर्दिष्ट की गई है इसके अन्तर्गत विविष्ट रूट/रास्ते पर प्रथम श्रेणी से गगली निम्न श्रेणी की वास-सुविधा भी है।

4. (1) राज्य व्यय पर उपलब्ध प्रवहन के अन्वया जब सड़क या स्टीमर द्वारा यात्रा कर रहा हो, मंत्री अपना वास्तविक यात्रा व्यय स्वयं अपने प्रमाण-पत्र पर कि प्रभारित की गई राशि वास्तविक रूप में संदत्त की गई है और इसके अन्तर्गत जलपान, होटल या रहने का बंगला का कोई प्रभार नहीं है, प्रभारित कर सकेगा अनुकल्पतः वह, यदि वह ऐसा चाहे, सड़क द्वारा यात्रा भत्ता ले सकेगा :-

(क) पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में तीन रुपये पच्चास पैसे प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ता;

(ख) परिवहन का वास्तविक व्यय:—

(i) छः की अधिकतम संख्या तक उसके व्यक्तिगत कर्मचारी; और

(ii) दौरे पर उपभोग के लिए ले जाए जाने वाले स्टोर सहित सभी सामान जिसे वह अपना व्यक्तिगत सामान बताया है; और

(ग) सड़क द्वारा खाली कारों के वहन के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में 70 पैसे प्रति किलोमीटर और मैदानी क्षेत्रों में 55 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ता ।

टिप्पण.—“वास्तविक व्यय” के अन्तर्गत रेलगाड़ी द्वारा और सड़क द्वारा परिवहन प्रभार भी है ।

(2) मंत्री जब सड़क या स्टीमर द्वारा यात्रा कर रहा हो तो मुख्यालय से प्रस्थान और पहुंचने के दिन के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता ले सकेगा :

परन्तु मंत्री जब सड़क द्वारा राज्य के व्यय पर उपबन्धित वाहन द्वारा यात्रा कर रहा हो तब मुख्यालय से प्रस्थान और पहुंचने के दिनों के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता ले सकेगी ।

5. (क) मंत्री सरकारी कार्य से, सरकारी यन्त्र या पब्लिक एअर ट्रांसपोर्ट कम्पनी के यन्त्र में भारत में किसी भाग की वायुमार्ग द्वारा यात्रा कर सकेगा ।

(ख) मंत्री, जब वायुमार्ग से यात्रा करेगा, वह वायु मार्ग द्वारा यात्राओं के लिए संदत्त किराया, यदि वस्तुतः संदत्त किया गया हो यात्री दरों पर रेलगाड़ी द्वारा या सड़क द्वारा सभी वैयक्तिक चीजबस्त के परिवहन का व्यय और छः से अनाधिक वैयक्तिक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम दरों पर वस्तुतः संदत्त किया गया रेलगाड़ी का किराया प्राप्त करने का हकदार होगा ।

वह अनुकल्पतः उतना यात्रा भत्ता जो प्रथम श्रेणी सरकारी कर्मचारी को नियमों के अधीन अनुज्ञेय है प्राप्त कर सकेगा । यदि, वायुमार्ग द्वारा यात्रा के किसी भी छोर पर मंत्री को सम्बन्धित यात्रा रेलगाड़ी द्वारा या सड़क द्वारा करनी हो तब वह उपरोक्त नियमों 3 और 4 के अधीन यात्राओं के लिए अनुज्ञेय यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकेगा । जबकि भूमि पर परिवहन, जो वायुमार्ग की यात्राओं का भाग हो और वह वायुमार्ग की यात्रा के लिए संदत्त किराए में सम्मिलित हो, के लिए कोई यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं कर सकेगा ।

6. मन्त्री, हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमाओं के बाहर भी सरकारी कारोबार के लिए यात्रा करने का हकदार होगा ।

7. मन्त्री, जब दौरे पर हो, उपरोक्त संदायों के अतिरिक्त 200 रुपये की दर पर दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा :

परन्तु:—

(i) मुख्यालय से प्रस्थान करने और पहुंचने के दिनों के लिए दैनिक भत्ता वह ही होगा जो नियम 3(छ) और 4(2) में उपबन्धित है ;

- (ii) मंत्री, जिसे हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर सरकारी दौरे के दौरान राजकीय अतिथि माना है, क मामले में उसका दैनिक भत्ता, यदि सरकारी तौर पर निशुल्क खानपान और आवास उपबन्धित किया गया है तो एक चौथाई भाग और यदि उससे खानपान या आवास में किसी के लिए प्रभार लिया है तो आधे पर सीमित होगा।

8. कार्यालय जाने के लिए मन्त्री, अपने घर से सरकार के मुख्यालय की यात्रा के संबंध में इन नियमों के अधीन सभी यात्रा भत्ता सुविधा का उपयोग कर सकेगा। कार्यालय छोड़ने पर मन्त्री को, सरकारी मुख्यालय से उसके घर तक समरूप सुविधाएँ अनुज्ञात होंगी।

9. (1) निम्न उप-नियम (2) के अध्वधीन, जब कोई मन्त्री, जिसके लिये शेष रेलगाड़ी आवास उपबन्धित किया गया हो या जो इन नियमों के अध्वधीन अध्यापेक्षा द्वारा रेलगाड़ी आवास आरक्षित करने का हकदार है, दौरे पर ऐसे आरक्षित आवास में यात्रा करता है पूर्ण खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(2) जब तक कि इन नियमों में यह अन्यथा अभिव्यक्त उपबन्धित न हो, आरक्षित आवास में मन्त्री के साथ यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति, प्रथम श्रेणी की अपेक्षित संख्या की टिकटों की खरीद द्वारा रेल को सामान्य किराया अवश्य मंदत करेगा, और आरक्षित आवास में की गई यात्रा के संबंध में, यात्रा भत्ते के प्रत्येक बिल में, आवास आरक्षित करने वाला मन्त्री, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने यात्रा की थी, विनिर्दिष्ट करेगा और यह प्रमाणित करेगा कि उनके द्वारा आवश्यक संख्या भी टिकटें क्रय की गई।

टिप्पणी.—(1) आवास आरक्षित करने वाला मन्त्री, यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व अपने साथ आरक्षित आवास में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए खरीदी गई टिकटों की संख्या और अन्य विवरण उस स्टेशन, जहाँ से यात्रा प्रारम्भ की गई, के स्टेशन मास्टर द्वारा अध्यापेक्षा प्राप्त पर प्रविष्टि करवाने को अपेक्षित होगा। यह रेल द्वारा भाड़ा, बमूल किए जाने के संबंध में सिविल और रेल विभागों के बीच समायोजन समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। जब ऐसे मन्त्री के मामले में, जो आरक्षित रेल आवास में यात्रा करता है, संपरीक्षा अधिकारी द्वारा कोई यात्रा भत्ता बिल प्राप्त नहीं किए जाने हैं किन्तु रेल अध्यापेक्षाओं के कारण केवल विकलन ही प्राप्त हुए हों, तब संपरीक्षा अधिकारी, मन्त्री से इस बारे प्रमाण-पत्र मांगेगा कि अध्यापेक्षा द्वारा तय की गई यात्रा लोक कर्तव्य से की गई थी।

- (2) यदि, निजी सचिव, आशुलिपिक या लिपिक के लिए मन्त्री के साथ आरक्षित आवास में होना लोकहित में आवश्यक हो तब वह ऐसा कर सकता है जब कि आरक्षित आवास में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या पहले ही रेल द्वारा आवास आरक्षित करने के लिए प्रभावित किराए की संख्या से अधिक हो:

परन्तु यह कि वह उस श्रेणी जिसमें वह यात्रा करने के लिए हकदार है, का टिकट खरीदता है, ऐसी दशा में, मन्त्री अपने यात्रा भत्ता बिल में यह प्रमाणित करेगा कि यह लोक सेवा के हित में था कि निजी-सचिव, आशुलिपिक या लिपिक उसके साथ आरक्षित आवास में यात्रा करता और यह कि उसने उस श्रेणी जिसके लिए वह हकदार था का टिकट क्रय किया था। टिकट का मूल्य रेल को संदय आरक्षित आवास के कर्षण के कारण प्रभार में से नहीं काटा जाएगा।

10. (1) एक मन्त्री 500/- रुपए प्रतिमास के वाहन भत्ते का हकदार है यह, किसी दिन जिसके लिए साधारण यात्रा भत्ता लिया जाता है, की कमी करने के अध्वधीन नहीं है। राज्य सरकार, यद्यपि, मन्त्री को वाहन भत्ते के स्थान पर सरकारी गाड़ी उपबन्धित करने को सक्षम है, और जब ऐसे सरकारी गाड़ी उपबन्धित की गई हो तब रख-रखाव और चलाने के लिए खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(2) जब सरकारी गाड़ी में दौरे पर यात्रा की जाए, तब मंत्री, दैनिक भत्ते का ही हकदार होगा। जब दौरे पर निजी यात्रा विराम के स्थान से सोलह किलोमीटर अर्धव्यास के भीतर की हो, निजी यात्राओं के लिए मंत्री से कोई भी प्रभार नहीं लिया जाएगा, किन्तु यात्राओं के ऐसे प्रभारों के लिए जो उपरोक्त सोलह किलोमीटर से अधिक हों, मंत्री, अपने व्यय पर पेट्रोल और मोबिल आयल उपबंधित करेगा:

परन्तु यह कि यदि विराम का स्थान दिल्ली है तो इस उपखण्ड में सोलह के लिए बत्तीस किलोमीटर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

टिप्पण.—कोई मंत्री जो 16 या 32 किलोमीटर अर्धव्यास से अधिक की निजी यात्रा के लिए सरकारी गाड़ी का प्रयोग करता है, यथास्थिति यात्रा भत्ता बिल पर निम्नलिखित प्ररूप में प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेगा:

“प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा सरकारी गाड़ी में 16/32 किलोमीटर अर्धव्यास से अधिक की गई, निजी यात्रा/यात्राओं.....पर..... सरकारी लेखे में खजाना बाऊचर/चालन नं०.....तारीख.....को वस्तुतः संदत्त किए गए”।

मंत्री जब राज्य मुख्यालय से बाहर हो, परन्तु यात्रा और दैनिक भत्ता प्रभारित नहीं करता, चिकित्सा उपचार और सरकारी कार्य के लिए स्थानीय प्रयोग के लिए राजकीय व्यय पर सरकारी गाड़ी का प्रयोग करने का हकदार होगा।

(3) लम्बे और खर्चीले दौरे पर जाने वाले मंत्री को, उसके व्यक्तिगत यात्रा व्यय को पूरा करने को पर्याप्त रकम का अग्रिम दौरे की समाप्ति पर या मार्च के 31वें दिन को, जो भी पूर्वतर हो उसको अनुज्ञेय यात्रा भत्ते की रकम के विरुद्ध समायोजन के अध्याधीन दिया जा सकेगा।

11. (1) जब मंत्री, अपने मुख्यालय के स्थान से बाहर, चाहे राज्य विधान मण्डल या संसद या किसी निकाय के निर्वाचन के संबंध में या अन्य किसी निजी कार्य के लिए स्वयं अपने व्यय पर या सरकार से भिन्न संगठन के व्यय पर जाता है, यदि निर्वाचन या उस निजी कार्य जिसके सम्बन्ध में वह गया था को अवरोध करके उसका मुख्यालय या राज्य में किसी अन्य स्थान पर वापस आना लोकहित में अपेक्षित है तो उसे, यथास्थिति, वातानुकूल/प्रथम श्रेणी रेल किराया या वायुयान द्वारा यात्रा के लिए किराया या रेल मोटर में एक सीट के लिए अनुमत्त किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि यदि रेल सेवा या अगली रेलगाड़ी के अभाव में मंत्री द्वारा, भाग में या पूर्ण यात्रा बल द्वारा, या निजी कारवा नाव द्वारा की जाती है तो उसको, इस प्रभाव के उसके प्रमाण-पत्र पर कि प्रभारित रकम वस्तुतः संदत्त की गई उसका वास्तविक यात्रा व्यय अनुमत्त किया जा सकेगा और जलयान, होटल या ठहरने के बंगले के लिए कोई प्रभार इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(2) मंत्री को उप-नियम (1) में वर्णित रियायत उस स्थान जहां से उसका आना लोक हित में अपेक्षित था, को उसको वापसी यात्रा में लिए भी अनुज्ञेय होगी, परन्तु ऐसी वापसी यात्रा उसके, यथास्थिति मुख्यालय या राज्य में किसी अन्य स्थान पर पहुंचने के चौबीस घण्टों के भीतर की गई हो।

12. मंत्री द्वारा भारत के बाहर, उसके सरकारी कार्यों के निर्वहन में किए गए दौरों के लिए, वह ऐसे यात्रा और दैनिक भत्तों का हकदार होगा जैसे कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले में अवधारित करे।

शिमला-2, 29 जनवरी, 1997

संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) 4(डी)-21/88.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा अनुपूरक उपबन्ध अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन "हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के यात्रा भत्ता नियम, 1971" का प्राधिकृत राजभाषा हिन्दी पाठ राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के सहर्ष आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा,

एम० एस० नेगी,
आयुक्त एवं सचिव।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के यात्रा भत्ता नियम, 1971

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के यात्रा भत्ता नियम, 1971 है।
 2. यह 25 जनवरी, 1971 से प्रभावी हुए समझे जाएंगे।
 3. अध्यक्ष निम्न वर्णित यात्राओं के लिए उसी मापमान से जो मंत्री को अनुज्ञेय है यात्रा भत्तों के लिए हकदार होगा :--
 - (क) जब कार्यालय में पदग्रहण करने जा रहा हो उसके निवास स्थान से विधान सभा के स्थान तक और पद त्याग करने के पश्चात् वापस उसके सामान्य निवास स्थान तक ;
 - (ख) भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन या समिति में हाजिर होने या प्रक्रिया, कार्यकरण और संगठन का अध्ययन करने के लिए किसी अन्य विधायी निकाय के स्थान का दौरा करने के लिए ;
- परन्तु अपने पदीय कर्तव्य के उन्मोचन में उस द्वारा भारत के बाहर किए गए दौरों के लिए, वह ऐसे यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों का हकदार होगा जो राज्य सरकार प्रत्येक मामले में अवधारित करे ;
- (ग) किसी लोक समारोह या राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय या कानूनी प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी समारोह में भाग लेने या किसी नागरिक सम्बोधन को प्राप्त करने या ऐसे सम्बन्धित बैठकों में भाग लेने के लिए या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या भागतः या पूर्णतः राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त निकाय द्वारा उपक्रम किए गए स्थलों या विकासशील या अन्वयिक कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए ;
 - (घ) विधान सभा का मुख्यालय बदले जाने की दशा में उसके गृह से यात्रा या जब वह वहीं निवास कर रहा हो तो मुख्यालय बदले जाने की दशा में विधान सभा के पुराने मुख्यालय से विधान सभा के नए मुख्यालय तक ;
 - (ङ) (1) विधान सभा के प्रत्येक सत्र के अन्त पर शिमला से उसके निर्वाचन क्षेत्र या सामान्य निवास स्थान तक और आगामी सत्र के आरम्भ पर शिमला के लिए वापसी यात्रा के लिए ;

- (2) जब विधान सभा दो या अधिक दिन के लिए स्थगित हुई हो, शिमला से उसके निर्वाचन क्षेत्र या सामान्य निवास स्थान तक और व्यवधान की कालावधि के पश्चात् वापस यात्रा के लिए और सत्र न होने की कालावधियों में मास में एक बार शिमला से उसके निर्वाचन क्षेत्र या सामान्य निवास स्थान तक और वापस ;

(च) कर्तव्य के निर्वहन में की गई ऐसी अन्य यात्राएं जो अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की जाएं ।

4. अध्यक्ष, मन्त्री के दैनिक भत्तों की ही दरों और उन्हीं शर्तों पर विराम भत्ते के लिए हकदार होगा ।

5. अध्यक्ष को, लम्बे और खर्चीले दौरे पर जाने के लिए, दौरे की समाप्ति या मार्च के इकत्तीसवें दिन जो भी पूर्वोक्त हो, समायोजन के अध्याधीन उसको अनुज्ञेय यात्रा व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि का अग्रिम दिया जा सकेगा ।

6. उपाध्यक्ष का यात्रा भत्ता/विराम भत्ता (1) उपाध्यक्ष उसी मापमान पर जो मन्त्री को अनुज्ञेय है निम्न-वर्णित यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते का हकदार होगा :

(क) जब कार्यालय में पद ग्रहण करने जा रहा हो, उसके निवास स्थान से विधान सभा के स्थान तक और पद त्याग करने के पश्चात् वापस उसके सामान्य निवास स्थान तक ;

(ख) (1) विधान सभा के प्रत्येक सत्र के अन्त पर शिमला से उसके निर्वाचन क्षेत्र या सामान्य निवास स्थान तक और आगामी सत्र के आरम्भ पर शिमला के लिए वापसी यात्रा के लिए ;

(2) जब विधान सभा दो या अधिक दिन के लिए स्थगित हुई हो, शिमला से उसके निर्वाचन क्षेत्र या सामान्य निवास स्थान तक और व्यवधान की कालावधि के पश्चात् वापस यात्रा के लिए और सत्र न होने की कालावधियों में मास में एक बार शिमला से उसके निर्वाचन क्षेत्र या सामान्य निवास स्थान तक और वापस ;

(ग) अध्यक्ष के आदेशों के अधीन उस द्वारा की गई यात्राओं के लिए :—

(1) भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने ; और

(2) उपाध्यक्ष के रूप में उसके कर्तव्यों से सम्बन्धित किसी अन्य कारोबार में हाजिर होने के प्रयोजन के लिए ।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को समय की बचत के लिए वायुयान द्वारा यात्रा करने के लिए अनुमत्त कर सकेगा, जिस दशा में वह वायुयान द्वारा यात्रा करने के लिए उसी मापमान पर जो उप-मन्त्री को अनुज्ञेय है, यात्रा भत्ते का हकदार होगा ।

(3) उपाध्यक्ष उन्हीं दरों और उन्हीं शर्तों पर जो मन्त्री को अनुज्ञेय है, दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(4) उपाध्यक्ष अपने स्वयं के यात्रा भत्ता बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अधिकारी होगा ।

7. उपाध्यक्ष को, लम्बे और खर्चीले दौरे पर जाने के लिए, दौरे की समाप्ति पर या मार्च के इकत्तीसवें दिन, जो भी पूर्वोक्त हो, समायोजन के अध्याधीन उसको अनुज्ञेय यात्रा भत्त की राशि के विरुद्ध, उसके व्यक्तिगत यात्रा व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि का अग्रिम दिया जा सकेगा ।

शिमला-2, 29 जनवरी, 1997

संख्या जी०ए०डी०-पी०ए० (4)-47/84. —हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा अनुपूरक उपबन्ध अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन “हिमाचल प्रदेश राज्य विधान अधिकारी, मन्त्री और सदस्य चिकित्सा सुविधाएं नियम, 1971” का प्राधिकृत राजभाषा हिन्दी पाठ राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के सहर्ष आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा;

एस० एस० नेगी,
आयुक्त एवं सचिव,

हिमाचल प्रदेश राज्य विधान अधिकारी, मन्त्री और सदस्य चिकित्सा सुविधाएं नियम, 1971

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधान अधिकारी, मन्त्री और सदस्य चिकित्सा सुविधाएं नियम, 1971 है।

(ii) ये नियम जनवरी, 1971 के पच्चीसवें दिन से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. अनुज्ञेय चिकित्सा सुविधाएं—तत्समय प्रवृत्त निम्नलिखित किसी पद को धारित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उसी प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा जो हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को उपलब्ध है :—

(i) हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य मन्त्री;

(ii) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष;

(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य के मन्त्री या उपमन्त्री; या

(iv) हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य :

परन्तु -

(क) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रतिपूर्ति दावे के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त होगी; और

(ख) प्रतिपूर्ति के आदेश देने के लिए समर्थ प्राधिकारी सुनिश्चित करेगा कि प्रतिपूर्ति के लिए दावा है और केवल प्रतिपूर्ति योग्य दवाईयों से सम्बन्धित ही है और अन्यथा उचित है।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए पद “उसके परिवार के सदस्य” से पति या पत्नी, यथा स्थिति ऐसा व्यक्ति जो उनके साथ रह रहा हो और पूर्णतय उस व्यक्ति पर निर्भर हो जैसे उसके विधिमान्य बच्चे उन्नीस सौ तेरह बच्चे, उसके वैध रूप से अपनाए गए बच्चे, उसके माता-पिता और उसकी विधवा पुत्रियां जो उनके साथ रह रही हों, पूर्णतयः उस पर निर्भर हों, अभिप्रेत है।

इन प्रयोजनों के लिए “परिवार के अन्तर्गत एक से अधिक पत्नी नहीं हैं।”

